भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं.4631
दिनांक 23 मार्च, **2020**

ओपेक और रूस के बीच समझौता

4631. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या **14** ओपेक देशों और रूस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर कए गए थे और इसे **2017** में कच्चे तेल के कम उत्पादन के लए एक वर्ष के लए लागू कया गया था;
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सौदा अगले नौ महीनों के लए बढ़ा दिया गया है;
(ग) क्या इस समझौते से ईंधन की कीमतों में वृद्ध होने की संभावना है और यदि हां, तो यह सौदा कस हद तक ईंधन की उच्च कीमतों और आ र्थक वकास को प्रभा वत करेगा;
(घ) क्या तेल की कीमतें **2019** के शुरू होने के बाद से **25** प्रतिशत बढ़ी है और व भन्न देशों के बीच संघर्ष का कारण बनी है; और
(ङ) यदि हां, तो हाल ही में ईंधन की कीमतों के आलोक में अ ग्रम कार्रवाई करने के लए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ) ओपेक और गैर-ओपेक तेल मंत्रियों ने कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्ध करने के उद्देश्य से दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 30 जून 2017 की अव ध, जिसे छः माह और बढ़ाया जा सकता है, के लए कच्चे तेल के उत्पादन में 1.2 म लयन बैरल की कटौती करने के लए वर्ष 2017 में वयना में एक करार कया है। बाद में ये देश मार्च 2020 तक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती जारी रखने पर सहमत हो गए।

ऐसी उत्पादन कटौतियों और साथ ही भू-राजनैतिक बदलावों से मूल्य में अस्थिरता आई है। 01 अप्रैल 2020 से उत्पादन में कटौती जारी रखने के लए ओपेक और गैर-ओपेक देशों के बीच आम सहमति नहीं होने तथा को वड-19 के कारण मांग में कमी आने से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में भारी गरावट आई है।

(ड.) भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी कंपनियां अपने तकनीकी और वा णज्यिक हितों पर निर्भर करते हुए व भन्न स्रोतों से कच्चा तेल प्राप्त करती हैं।

****